भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1436

07 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण

1436. कुमारी गोड्डेति माधवी:

श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार ने देश भर में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें जिला बैंकों, राज्य सहकारी बैंको और नाबार्ड से जोड़ने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों को ब्यौरा क्या है जिन्होंने उपरोक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन पहले ही शुरू कर दिया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री

(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना नाबार्ड और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है। उत्तराखंड और तेलंगाना ने पैक्स की कुछ कार्यात्मकताओं को कम्प्यूटरीकृत किया है।

****